भारतीय रेल्वे मजदूर संघ

(संलग्न - भा. म. संघ व स. क. रा. प.)

तेरहवां त्रैवार्षिक अधिवेशन

दि. 30 सित. तथा 01 अक्टू., 2001

अध्यक्ष का भाषण

राजर्षि टंडन मण्डपम्, प्रयागराज

[इलाहाबाद]

✤ प्रधान कार्यालय ✤

33, मोती भुवन, दूसरी मंजिल, डॉ. डिसिल्वा रोड,

दादर (प.), मुंबई - 400 028.

फोन : 422 4084

भारतीय रेल्वे मजदूर संघ

(संलग्न - भा. म. संघ व स. क. रा. प.)

तेरहवां त्रैवार्षिक अधिवेशन

दि. 30 सित. तथा 01 अक्टू., 2001

राजर्षि टंडन मण्डपम्, प्रयागराज [इलाहाबाद]

परम् आदरणीय श्रीमान दत्तोपंत ठेंगडीजी, श्री. गिरीश अवस्थीजी, श्री. अमलदार सिंहजी, पधारे हुए अतिथिगण, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, प्रतिनिधि बन्धुओं और बहनों,

ईसा की नयी शताब्दी, नयी सहस्त्राब्दी में आयोजित किये गये भारतीय रेल्वे मजदूर संघ के तेरहवें त्रैवार्षिक अधिवेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तीन वर्ष पूर्व हम मुंबई में मिले थे। तीन वर्षो का यह कालखण्ड सम्पूर्ण मानव जाति के, विशेष कर भारतवासियों और इनमें भी मजदूरों के लिए अत्याधिक निराशाजनक रहा। दुनिया भर में आर्थिक मंदी व्याप्त है। उद्योग, व्यापार आदि उत्साहवर्धक स्थिति में नहीं हैं। धार्मिक जेहाद के नाम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर मध्य पूर्व में ईरान, ईराक तक में आतंकवाद जोर-शोर से बढ़ रहा हैं। आतंकवाद मानव समूह के लिए एक चुनौती बन गया है। अभी हाल की स. रा. अमेरिका में की गयी आतंकवादी कार्यवाही में लगभग 64 देशों के दस हजार से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गये । पूरी दुनिया इस घटना से स्तब्ध रह गयी है। निःसंदेह यह अब तक की दुनिया की सबसे भयानक आतंकवादी घटना हैं। हमें अपने पडोसी देशों पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, म्याभार, श्रीलंका में हो रही घटनाओं से चिन्तित होना स्वाभाविक है। कश्मीर में की गयी शस्त्रविराम की घोषणा के तुरन्त बाद निर्दोष लोंगो की हत्याओं का सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया है। अमरनाथ यात्रियों की बम बिस्फोट में हत्या करके उन्होंने अपने इरादों एवं संस्कृति का परिचय ही दिया है। कश्मीर में प्रतिदिन भीषण ह्रदयविदारक नरसंहार

किया जा रहा है। दूसरी ओर बांगलादेश जैसे छोटे से सामान्य देश ने हमारे सैनिकों की निर्मम हत्या की, जबकि बांगलादेश का निर्माण ही भारत की सहायता से हुआ था। शस्त्र विराम से कश्मीर में धोखा खाने के बावजूद पूर्वोत्तर राज्य नगालैण्ड में इसे लागू किया गया हैं। इससे वहां की समस्या और जटिल बन गयी है। त्रिपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपहरण करके दो वर्ष तक घोर प्रताड़ना देने के बाद उनकी क्रूर हत्या कर दी गयी। देश की अखंडता संप्रभुता, एकता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए इन चार स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे निश्चित रूप से शहीद हुए हैं। किन्तु खेद इस बात का है कि इनके सर्वोच्च बलिदान पर सरकार सहित विभिन्न क्षेत्र के लोग और प्रचार माध्यम मौन रहे।

देश भर में सेवा के नाम पर धर्मान्तरण का खेल खुलेआम चल रहा है। हम सब कुछ क्यों सहन करते जा रहे हैं, यह समझ से परे हैं। कहीं हमने अपनी सारी संवेदनशीलता ही तो नहीं खो दी है। हमारी संस्कृति , संस्कार, परम्परा, रीति - रिवाज, भाषा, विचार, इतिहास इत्यादि के अतिरिक्त उद्योग, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान, संपदा और देश की सीमा पर तीव्र आघात पहुंचाया जा रहा है और हम यह सब चुपचाप सहन करते जा रहे हैं। इस पर भी हमारे ऊपर कट्टरवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है। चिन्ता की बात यह है कि हमारे ही तथाकथित बुध्दिवादी, प्रगतशिल कहाने वाले लोग जान-बूझकर प्रयत्नपूर्वक भारतीय जन मानस की अस्मिता, निष्ठा और राष्ट्र के प्रति अगाध श्रध्दा पर नित्य आघात करने में आनन्द का अनुभव करते हैं। इन्ही सब बातों से देश दुर्बल बनता है। यह जानते हुए भी ये लोग अनजान बनते हैं। दासता का सैकडो वर्षों का कटु अनुभव ये कैसे भूल रहे हैं। इस प्रकार की उनकी हरकतें देश को पुनः दासता की जंजीरों में जकडने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। ये लोग देश को वैचारिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। किन्तु इनकी यह साजिश कतई सफल नहीं होने पायेगी। देश की परिस्थितियों का आकलन करने वाले किये जा रहे सभी आक्रमणों को अच्छी तरह समझने वाले और इन आक्रमणों को विफल करने के लिए जान की बाजी लगाने वाले देशभक्तों के प्रयास से सारे हथकंडे असफल हो जायेंगे। ऐसा सिर्फ कहने या इच्छा करने मात्र से नहीं होगा। इसके लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित सभी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सजग तथा सतर्क

रहने की नितांत आवश्यकता है। सरकार पर निर्भर रहकर चुपचाप देखते रहेंगे तो हम सभी इन घटिया विचार के राक्षसों के शिकार बन जायेंगे। ऐसा लगता है सरकार का ध्यान इन बातों पर नहीं है। इसीलिए तो आवश्यकता है कि हम सभी जागृत रहें और देशद्रोहियों की हर चाल हर प्रहार का मुकाबला करते हुए प्रत्याघात करें। सिर्फ आत्मरक्षा ही पर्याप्त नहीं है अब।

खुली अर्थव्यवस्था, भूमण्डीकरण तथा विश्व व्यापार संगठन की कुटिल नीतियां के कारण देश के उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक क्रिया कलापों पर हमले हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में कारोबार की छूट देकर बैक, बीमा जैसे महत्वपूर्ण उद्योंगो में इनके प्रवेश का मार्ग आसान कर दिया गया है। प्रिन्ट मीडिया, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे प्रभावशाली माध्यमों द्वारा विदेशी उत्पादों का खूब प्रचार किया जा रहा है। विदेशी वस्तुओं से भारतीय बाजार भरता जा रहा है। परिणाम स्वरुप एक-एक करके देशी उद्योग या तो बन्द होते जा रहे हैं या फिर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खरीद लिए जा रहे हैं। इन सबका परिणाम व्यापार पर भी पड रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पर चतुर्दिक संगणकीकरण, यंत्रीकरण तथा निजीकरण किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। मजदूरों की छंटनी की जा रही है। अत्यधिक बेरोजगारी बढ़ने के कारण सामाजिक ढ़ांचा ही ध्वस्त होता नजर आ रहा है। सरकार ने निश्चय कर लिया है कि कर्मचारियों की संख्या में व्यापक कटौती की जायेगी। नयी नियुक्ति पर काफी दिनों से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इससे भी अवकाश प्राप्त करने तथा असमय मौत के कारण कर्मचारियों की संख्या अपने आप घटती जा रही है। इतने पर भी स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना (VRS) लागू की जा रही है। लालच दिखाकर कर्मचारियों को यह योजना स्वीकार करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है। एक प्रकार से स्वेच्छा निवृत्ति न होकर "दबाव निवृत्ति" है। हाल ही में स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना के तहत अवकाश प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारियों को अत्यन्त कटु अनुभव प्राप्त हो रहा है। उनका परिवारिक जीवन छिन्न-भिन्न हो रहा है। और दूसरी ओर बैंकों में कार्यक्षमता निम्नतर होती जा रही है। बचे हुए अकुशल कर्मचारियों के कारण ग्राहकों को नित्य परेशानी उठानी पड़ रही है। कुशल एवं कार्यक्षम कर्मचारियों को घर में बैठाकर अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार की वैयक्तिक एवं सामाजिक कुरीतियों,

समस्यायों का सृजन किया जा रहा है । नये रोजगार के सृजन हेतु सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है । लोगों को स्वरोजगार निर्माण की सलाह दी जा रही है । ऐसी परिस्थिति में देश की कार्यशील जनता, आम नागरिक तथा मजदूरों का भविष्य एकदम अंधकारमय होता जा रहा है । मुद्रास्फीति में अनवरत् बनी अस्थिरता के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है । बैंको में जमा धनराशि पर धीरे-धीरे निरंतर ब्याज दर कम की जा रही है । जीवन-यापन अत्यन्त कठिन, दुस्सह होता जा रहा है । नौकरी है नहीं, व्यवसाय चल नही रहे, जीवन - निर्वाह का कोई अन्य मार्ग है नहीं, अनाजों की बिक्री से पर्याप्त मूल्य न मिल पाने से कृषि अलाभकारी स्थिति में पहुंच गयी है । पशुपालन भी अत्याधिक व्ययसाध्य होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय ? यह एक जटिल प्रश्न बना हुआ है । बेरोजगार नवयुवकों के सम्मुख ज्यादा अंधकार छाया हुआ है । वे अपने कैरियर को लेकर चिन्तित है । परिणामतः बहुत बार गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं । उनकी मानसिकता परिवर्तित हो रही है । भौतिकवादी जीवन की ओर रुझान बढ़ रहा है । नैतिक मूल्यों के प्रति चिन्ता ही नहीं दिखाई दे रही है । परिणाम स्वरुप बिना मेहनत किये कम समय में जल्दी से जल्दी अधिकाधिक धन अर्जित करने की होड़ सी लगी हुई है । इसके लिए वे कोई भी मार्ग स्वीकारने में नहीं हिचकतें । यही कारण है कि गबन धोखाधडी, आर्थिक अपराध जन्म ले रहे हैं । दिन दहाडे खून - खराबा, लूटमार, डकैती, मँगवार अब सामान्य बात हो गयी है । गांव से लेकर महानगरों तक चर्तुर्दिक यही वातावरण है । इन सब का सम्बन्ध सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से जुडा हुआ है । और सरकार देश की दुर्दशा की चिन्ता किये वगैर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन के दबाव में एक के बाद एक श्रम विरोधी, राष्ट्र के लिए अहितकारी आर्थिक निर्णय लेती जा रही है । सरकार को भले ही इन सब की चिन्ता न हो किन्तु राष्ट्रभक्त मजदूर इस बारे में अवश्य चिन्तित है । सरकार की इन सभी नीतियों के विरोध में "WTO मोडो तोडो छोडो" के उद्‌घोष के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में लाखों मजदूरों ने दिल्ली में विशाल जुलूस निकालकर तथा रैली करके अपना रोष प्रकट किया है । इस रैली में श्री. दत्तोपंत ठेंगडी जी ने इशारे में ही चेतावनी दे दी है । उनकी इस चेतावनी को प्रचार माध्यमों ने खूब जोरदार तरीके से उठाया । कई दिनों तक देश भर में इस सम्बन्ध में चर्चा चलती रही ।

भारतीय रेल्वे मजदूर संघ तथा संलग्न युनियनों की मान्यता के सम्बन्ध में इस कालखण्ड में काफी प्रयास किये गये। कई बार रेलमंत्री, रेल राज्यमंत्री, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड इत्यादि सर्व सम्बन्धित व्यक्तियों बातचीत हुई। कागजात सौपे गये। इस सम्बन्ध में सारे तर्क प्रस्तुत किये गये। उनकी तरफ से उठाये गये सभी प्रश्नों तथा शंकाओ का निराकरण किया गया। गलत धारणाये दूर की गयी। इतना सब होने पर भी रेलवे बोर्ड की मान्यता न देने की मानसिकता तथा दोनो मान्यताप्राप्त संगठनों के विरोध के कारण मान्यता देने में विलम्ब किया जा रहा है। "एक उद्योग, एक संगठन" यह आदर्श कल्पना महज कागजी है। जब पहले से ही दो संगठन विद्यमान है, तो तीसरा क्यों नही हो सकता ? केन्द्र सरकार के ही प्रतिष्ठानों पोस्ट, प्रतिरक्षा में तीन-तीन मान्यता प्राप्त संगठन है तो रेलवे में अलग से विचार करने की आवश्यकता क्या है ? मान्यता के सम्बन्ध में सारी शर्तें हमने कब की पूरी की है। पैंतीस वर्षो से बिना मान्यता के यह संगठन कार्यरत है। लाखों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यही एक तथ्य हमें मान्यता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। किन्तु मान्यता न देकर हम राष्ट्रवादी कर्मचारियों पर अन्याय करने का सिलसिला चल रहा है। यह लोकतन्त्र की घोर विडम्बना नहीं तो और क्या है। युनियन का उपयोग मजदूरों के हित के साथ ही रेल उद्योग और राष्ट्र की समृध्दि बढ़ाने हेतु, यात्रियों तथा व्यापारियों को समुचित सुविधा देने हेतु हम करना चाहते है। "कार्य की संस्कृति" को बढ़ावा देना चाहते है। हमारे इस सदहेतू को सफल न होने देने के लिए सारे संगठन और प्रशासन एकजुट हो गया है। उन्हे डर है कि बिना कार्य किये वेतन, सुविधा, अन्य लाभ प्राप्त करते रहने पर रोक लग जायेगी। हमारे निस्पृह कार्यकर्ता यह अन्धेर गर्दी अधिक दिन तक नहीं चलने देंगे। यह सब जानते हुए भी शासन हताश होकर हमें मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। भारतीय रेल्वे मजदूर संघ ने गत् 23 जून, 2000 को नई दिल्ली में रेल भवन पर अपनी मान्यता सम्बन्धी एक सूत्री मांग के साथ प्रदर्शन किया था। पूरे देश के हजारों रेल कर्मचारी जुलूस-प्रदर्शन में शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस की बेवजह की गयी अड़चन पैदा करने की कोशिश के बावजूद कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा। रेल राज्यमंत्री स्वयं मोर्चे के सम्मुख उपस्थित हुए और कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि गैर जिम्मेदार वेस्टेड इंटरेस्ट लोग नहीं चाहते कि भारतीय रेल्वे मजदूर संघ को मान्यता

मिले। इस प्रदर्शन को खूब प्रचार मिला तथा प्रशंसा की गयी। समाचार पत्रों तथा दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों ने खूब प्रचार किया।

हमें न्याय नहीं मिल सका। सरकार से हमारी जायज मांग को पूरी करने की उम्मीद सार्थक नहीं हो सकी। यद्यपि हम सरकार की मजबूरी भली - भांति जानते हैं किन्तु क्या सरकार से हम इतनी अपेक्षा भी नही कर सकते कि कार्यकर्ताओं पर बिना किसी कारण के किये जा रहे अनाचार, अन्याय, प्रताड़ना, जबरन मानसिक आघात और उत्पीडन से प्रशासन को रोका जाय। दोनो मान्यता प्राप्त संगठनों के बहकावे में आकर प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह सब जानते और समझते हुए भी शासन मौन है। उसकी निष्क्रियता संदेहास्पद हो गयी है। भारतीय संविधान में दियें गये लोकतांत्रिक मौलिक अधिकारों से भी हमें वंचित रखा जा रहा है। ट्रेड युनियन अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। धरना देना, प्रदर्शन करना, अन्याय के विरोध में द्वार सभा करना हमारे लिए वर्जित है। आदेश निकालकर प्रतिबन्धित किया जाता है। ट्रेड युनियन अधिकार हमारे लिए नहीं अन्य लोंगों के लिए है। इतनी बडी असंवैधानिक बात इसी शासन काल में करने की हिम्मत नौकरशाही कर रही है। प्रताड़ना की कार्यवाही प्रत्येक जोन में हो रही है। ट्रेड युनियन अधिकारों का उपयोग करने पर निलंबन, चार्जशीट देना, स्थानान्तरण, नौकरी से निकालने की कार्यवाही अंधाधुंध की जा रही है। इस सरकार से हमने जितनी आशायें की थी उतनी ही घोर निराशा हो रही है। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी बिना विचलित हुए हमारे कार्यकर्ता संगठन का कार्य कर रहे हैं। संगठन में अविचल निष्ठा, मजदूरों के हित में ह्रदय से कार्य करने भी अभिलाषा, निस्वार्थ भाव से सतत् कार्य करते रहना, अपने ध्येय पर दृढ रहकर कंटका कीर्ण पथ पर चलना, मार्ग की अड़चनों, कठिनाईयों से विचलित न होना इत्यादि ही हमारे कार्यकर्ताओं का वास्तविक परिचय है।

वित्तमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ. राकेश मोहन कमेटी ने सुधार सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट रेलवे को दे दी है। रेलवे का खर्च कम हो और विदेशों में चल रही पध्दति यहां भी लागू करने के उद्देश्य से सिफारिश की गयी है। यद्यपि कमेटी के सदस्यों में अधिकांश यहां की स्थिति मजदूरों की मानसिकता यात्रियों की आवश्यकता, रेलवे के कारोबार इत्यादि से

अनभिज्ञ है । इस रिपोर्ट में रेलवे का निजीकरण, स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना लागू करना, कर्मचारियों की संख्या कम करना, रेलवे को कार्पोरेशन में परिवर्तित करना, कर्मचारियों को दी जानेवाली बुनियादी सुविधाओं को समाप्त करना इत्यादि शामिल है । भारतीय रेलवे मजदूर संघ इन सिफारिशों का तीव्र विरोध करता है । जून, 2001 में चेन्नई में आयोजित "उत्पादन इकाईयां एवं कारखाना सम्मेलन" में हमने अपना स्पष्ट विरोध प्रकट किया था । आज इस अधिवेशन के माध्यम से हम अपील करते हैं कि अपने छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाकर एक साथ एकत्रित होकर इस षडयंत्र का मुकाबला करना है, अन्यथा अत्यन्त संघर्ष और परिश्रम से प्राप्त की गयी सुविधाओं, अपने हित में बनाये गये नियम - कानून अधिकार इत्यादि से हम हाथ धो बैठेंगे । सर्व शक्तिमान व्यवस्था के विरोध में जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी । यह लड़ाई मजदूर संगठन ही लड़ सकते है, अन्य कोई नहीं । सुयोग से नियति मे यह जिम्मेदारी हमें सौपी है । आइये, हम सब मिलकर इस घिनौनी साजिश का डटकर मुकाबला करें । हमें पूर्ण विस्वास है कि अन्य संगठन भी इस पर विचार करके ठोस निर्णय लेंगे । धन्यवाद !

भारत माता की जय !

दत्ता रावदेव

अध्यक्ष

भारतीय रेल्वे मजदूर संघ